अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 04 | श्री विजय पुरम, रविवार , 04 जनवरी 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अण्डमान निकोबार में 373 करोड़ रूपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

ग्रेट निकोबार परियोजना से यह द्वीप वैश्विक कार्गो हब, पर्यटन केंद्र और भारत की सामरिक सुरक्षा का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्तंभ बनेगा

जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों ने पीड़ा को शक्ति और यातना को स्वाधीनता के संकल्प में बदला, वह अण्डमान–निकोबार हर भारतीय के लिए तीर्थभूमि है

मोदी सरकार अण्डमान–निकोबार में पर्यावरण की रक्षा करते हुए विरासत का संरक्षण कर इसे विकसित भारत में कंट्रीब्यूटर बना रही है

नई दिल्ली, 3 जनवरी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज श्री विजय पुरम में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, श्री बंडी संजय कुमार, अण्डमान तथा निकोबार के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के अध्यक्ष एडमिरल श्री डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय और केन्द्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्री विजय पुरम में तीन नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का लोकार्पण भी किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इसी भूमि पर अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई सेल्यूलर जेल में आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले कई बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का लंबा समय काटा। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने यहां दम तोड़कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मज़बूती दी और कई वीर यहां फांसी के तख्ते पर लटका दिए गए। उन्होंने कहा कि आज सेल्यूलर जेल में बना वीर सावरकर का स्मारक और प्रज्वलित मशाल पूरी दुनिया को बता रही है कि यहां कई महान आत्माओं ने

शेष पृष्ठ 4 पर

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की

मोदी सरकार ने न्याय प्रणाली के पांचों स्तंभों – पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक व प्रोसिक्यूशन का पूर्ण आधुनिकीकरण किया

नए आपराधिक कानूनों से जाँच में तेजी आ रही है और दोष सिद्धि दर भी बढ़ रही है

ई–एफआईआर और ज़ीरो–एफआईआर गरीबों व महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही हैं

नई दिल्ली, 3 जनवरी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज अण्डमान–निकोबार द्वीपसमूह के श्री विजय पुरम में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का विषय सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री (सीएफएसएल) और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) था। बैठक में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, श्री बंडी संजय कुमार, संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य, गृह सचिव, एनएफएसयू के कुलपति और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर–डी) के महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 2019 से लेकर अब तक संसदीय परामर्शदात्री समिति की 12 बैठकें की हैं, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन है कि नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद समय पर न्याय मिले। श्री शाह ने कहा कि हम 2029 तक ऐसी व्यवस्था बनाएँगे जिसमें तीन साल की अवधि में एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 2022 से अब तक हुए सुधार इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। गृह मंत्री ने कहा कि एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय तक की पूरी प्रक्रिया तीन साल में पूरी करने की कल्पना को हक़ीक़त में बदलने के लिए गृह मंत्रालय इन प्रयासों की 360 डिग्री मॉनिटरिंग कर रहा है और कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री अमित शाह ने कहा कि न्याय देने की प्रक्रिया के लिए

शेष पृष्ठ 4 पर

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने प्रदर्शनी मैदान में न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

श्री विजय पुरम, 3 जनवरी

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज प्रदर्शनी मैदान, श्री विजय पुरम में न्याय संहिता पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार, माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी, एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.), केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पुलिस महानिदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, आयुक्त–सह–सचिव (गृह), आयुक्त–सह–सचिव (राजस्व/जहाज़रानी) और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता

शेष पृष्ठ 4 पर

जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस), जो 2 से 4 जनवरी, 2026 तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दौरे पर हैं, ने आज लोक निवास, श्री विजय पुरम में माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी, एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान द्वि–उपयोगी सामरिक अवसंरचना, नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों, रनवे के उन्नयन/विस्तार, गहरे पानी के बंदरगाहों, परिप्रेक्ष्य योजनाओं तथा तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने प्रदर्शनी मैदान में न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

श्री विजय पुरम, 3 जनवरी

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज प्रदर्शनी मैदान, श्री विजय पुरम में न्याय संहिता पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार, माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी, एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.), केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पुलिस महानिदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, आयुक्त–सह–सचिव (गृह), आयुक्त–सह–सचिव (राजस्व/जहाज़रानी) और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता

शेष पृष्ठ 4 पर

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज श्री विजय पुरम में

पृष्ठ 1 का शेष

अपना बलिदान दिया था। श्री शाह ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले आज़ाद भारत की इसी भूमि पर तिरंगा फहराया था और उन्ही की स्मृति और उनके उदगारों के सम्मान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दो द्वीपों के नाम शहीद और स्वराज रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस द्वीपसमूह पर हर द्वीप को स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीरों का नाम देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह भूमि आज़ाद भारत के हर नागरिक के लिए एक तीर्थभूमि है क्योंकि यहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पीड़ा को शक्ति, एकांत को संकल्प और यातना को स्वाधीनता तक सहन कर स्वतंत्रता प्राप्त की थी।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस द्वीपसमूह को सामरिक शक्ति के रूप में परिवर्तित किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अण्डमान–निकोबार को देश के खजाने पर बोझ मानती थी, मोदी सरकार में यह देश के खजाने में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में आया यह बदलाव देश के कण कण को भारत माता मानकर उसे समर्पित रहने के संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इसके तहत आज यहां नौ बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 2 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है और एक ही दिन में 373 करोड़ रूपए के विकास के उपहार इस द्वीपसमूह को मिले हैं। श्री शाह ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं में 229 करोड़ की लागत वाला एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र शामिल है। उन्होंने कहा कि 33 करोड़ की लागत से ज़िला अस्पताल चरण–1 का लोकार्पण, फॉरेंसिक साइंस लैब का लोकार्पण और 50 करोड़ रूपए की लागत से 6 अन्य योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि आज इन विकास परियोजनाओं के माध्यम से हमारे द्वीपसमूहों के विकास के एक नए अध्याय की शुरूआत हो रही है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज यहां तीन नए आपराधिक कानूनों का परिचय देने वाली एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इस प्रदर्शनी को ज़रूर देखना चाहिए जिससे उन्हें आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली में आने वाले आमूलचूल परिवर्तन और तकनीक को मिलने वाले कानूनी आधार के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि यहां के सभी वकीलों, युवा विद्यार्थियों, विशेषकर महिलाओं, को इसे ज़रूर देखना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशभर में गुलामी की निशानियों से मुक्ति पाने का अभियान शुरू किया है और इसीलिए नेताजी के नाम पर पोर्ट ब्लेयर का नामकरण श्री विजय पुरम और हमारे वीर सेनानियों के नाम पर द्वीपों का नाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह एक प्रकार से हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता, समुद्री शक्ति और आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि अण्डमान निकोबार में एक ओर जहां ब्लू इकोनॉमी और पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं, वहीं आज़ादी के आंदोलन की एक अमूर्त प्रतिकृति के रूप में हर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति भी यहां देखी जा सकती है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार विरासत को खोए बिना पर्यावरण को सुरक्षित और सुरक्षा को सुदृढ़ रखते हुए इस द्वीपसमूह को पूर्ण विकसित भारत का हिस्सा बनाने के प्रति कटिबद्ध है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पर्यटन हो या पर्यावरण, मत्स्य संपदा हो या कृषि, एमएसएमई हो या स्वच्छ ऊर्जा, हर क्षेत्र में विकास की शुरूआत यहां हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रेट निकोबार में आने वाला प्रोजेक्ट पूरे विश्व के नक्शे पर अण्डमान निकोबार को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान और सामरिक सुरक्षा का केन्द्र बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के एक दशक बाद यह स्थान दुनिया के सबसे अधिक पर्यटकों द्वारा भ्रमण किए जाने वाला स्थान बन जाएगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि स्कूबा डाइविंग के आईएसओ मानांकों के अनुरूप अण्डमान निकोबार को अपग्रेड कर हमने इसे वैश्विक स्कूबा और एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का गंतव्य बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पेड़ मां के नाम अपील के तहत यहां 24 लाख वृक्षों का रोपण कर हमने पर्यावरण की भी चिंता की है। उन्होंने कहा कि श्री विजय पुरम नगरपालिका पालिका परिषद द्वारा 98 प्रतिशत घरों से कचरा संग्रहण किया जाना स्वच्छ भारत मिशन की ऐतिहासिक सफलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का 11वें से चौथे नंबर का अर्थतंत्र बन गया है और 2 ही साल में हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि देश में आर्थिक विकास हो रहा है, हम दुनिया के उत्पादन का हब बन रहे हैं, देश सुरक्षित हो रहा है और परंपराओं को पुनर्जीवित कर अपनी संस्कृति और इतिहास के आधार पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लोगों ने हर क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तन कर सर्वांगीण विकास का नया अध्याय गढ़ने का काम किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है और देश की 130 करोड़ जनता को संकल्प दिलवाया है कि आज़ादी की शताब्दी के समय हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भर भारत और भारतीयों के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा और हर भारतीय को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प भी लेना होगा।

इस अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के अध्यक्ष एडमिरल श्री डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) ने उपस्थित जन समूह को नववर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि एविस द्वीप, लॉन्ग आइलैंड, शहीद द्वीप तथा श्री विजय पुरम स्थित मेगापोड रिज़ॉर्ट–इन चारों मेगा पर्यटन पीपीपी परियोजनाओं के निविदा को अंतिम चरण में सफल बिडर्स के चयन को स्वीकृति प्रदान करने के लिये समस्त द्वीपवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। इनमें राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित आतिथ्य श्रृंखला सम्मिलित हैं, जिनसे द्वीपों की पर्यटन अवसंरचना में एक पैरडिग्म शिफ्ट आयेगा तथा पर्यावरण उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ–साथ व्यापक रूप से रोज़गार सृजन और स्थानीय उद्यमिता को स्थायी आधार प्राप्त होगा।

उप राज्यपाल ने कहा कि इसके अतिरिक्त, पीपीपी मॉडल पर आधारित 11 प्रमुख पर्यटन परियोजनाएँ अन्तिम चरण में हैं और कुछ ही दिनों में एसएफसी एवं पीपीपीएसी की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाएँगी। साथ ही, इसके अगले चरण के लिए नए पर्यटन स्थलों की पहचान की गई है, जहाँ विकास का फोकस गुणवत्ता तथा सतत और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर है। हमारा उद्देश्य है कि द्वीपसमूह वैश्विक स्तर पर हाई–वेल्यू, लो–इम्पैक्ट मॉडल पर प्रीमियम टिकाऊ पर्यटन गंतव्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करे। उन्होंने कहा कि द्वीपों के समग्र विकास के लिए द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) के मार्गदर्शन में कनेक्टिविटी व सामरिक अवसंरचना विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में लगभग 1 लाख करोड़ रूपए का ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी), नया ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट, पॉवर और इंटिग्रेटड टाउनशिप को चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जा रहा है। डीपीआर के अनुसार आईसीटीटी की क्षमता फेस–1 में 5.8 मिलियन ट्वेंटी–फुट इक्वलेंट यूनिट (टीईयू) होगी, जिसे आगे बढ़ाकर अन्तिम चरण तक 20.4 मिलियन टीईयू किया जाएगा। मलाका स्ट्रेट को डोमिनेट करती आईसीटीटी की सामरिक स्थल को देखते हुये यह देश ही नहीं, समग्र भारत–प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह में से एक की क्षमता रखेगा। पीपीपी मॉडल पर विकसित यह परियोजना भारत की वैश्विक मैरिटाइम ट्रेड में भूमिका तथा भारत–प्रशांत में आर्थिक सामरिक उपस्थिति को सुदृढ़ करेगी।

उन्होंने कहा इसी परियोजना के अंतर्गत ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित नये ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट्स के डीपीआर को संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और हाल ही में केबिनेट कमेटी ऑन सेक्यूरिटी द्वारा इसे जोइंट यूज़र ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट एवं नेवल एयर स्टेशन के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना द्वीपों की सामरिक तत्परता के साथ–साथ नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं को भी दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित करती है। एयर कनेक्टिविटी के संदर्भ में द्वीपों में उड़ान योजना के अंतर्गत फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट व सी प्लेन सेवायें भी शीघ्र ही आरंभ होने के लिये हम कार्यरत हैं। समानांतर रूप से, श्री विजय पुरम में प्रस्तावित नए ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट के लिए फाइनल साइट सेलेक्शन और लेडार सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात आगामी प्रक्रियाएँ स्वीस्कृति के लिए प्रेषित हैं।

उन्होंने कहा कि समुद्री अवसंरचना के क्षेत्र में पीपीपी तथा लैंडलोर्ड मॉडल पर हमारे द्वारा प्रस्तवित अटलांटा बे डीप–वाटर पोर्ट एक परिवर्तनकारी पहल है। मंत्रालय के निर्देश पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ऑथोरिटी द्वारा यहाँ डीप–वाटर ड्राई बल्क ट्रांसशिपमेंट तथा बहुद्देशीय पोर्ट हेतु टेक्नो–कमर्शियल फीसबलिटी स्टडी एवं बिजनेस प्लान तैयार किया जा रहा है। आईआईटी मद्रास के प्रारंभिक आकलन में 4 किलोमीटर प्रस्तावित है, जबकि इंडीपेंडेंट प्रोफेशनल्स के अनुसार इसके एक नेचुरल हार्बर होने से 7–8 किलोमीटर जेटी न्यूनतम निकर्षण और बिना ब्रेकवाटर के संभव है, जिससे यह जेटी आकार के आधार पर भारत के शीर्ष 3 बंदरगाहों में सम्मिलित हो सकता है। यह परियोजना भारत की मेरिटाइम लॉजिस्टिक्स ऑटोनोमी को सुदृढ़ करेगी।

उप राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2017 तक इन द्वीपों का लगभग समस्त भाग ही ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिये नो–गो ज़ोन था। हमारे निरंतर प्रस्तावों से तथा इसे द्वीप विकास एजेंसी के एजेंडा में सम्मिलित किये जाने के बाद ओफशोर नो–गो ज़ोन्स के पुनर्निर्धारण से 3 लाख 81 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए खुला और ऑयल इंडिया एवं अन्य एजेंसियों को अण्डमान बेसिन में उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसकी कमर्शियल वायबिलिटी सुनिश्चित होने पर भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा तथा स्ट्रेटजिक ओटोनोमी पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो कि एक गेम चेंजर सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि एक साल पहले आईडीए की सातवीं बैठक में शत–प्रतिशत डीडीज़लाइज़ेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अनुपालन में श्री विजय पुरम के होप टाउन में 50 मेगावाट एलएनजी–बेस्ड पॉवर प्लांट एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनवीवीएन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ईपीसी और सिविल कार्य के लिए निविदाएँ जारी की जा चुकी हैं और बिड ओपनिंग इसी माह प्रस्तावित है। यह पहल न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स और सम्बद्ध सेवाओं में स्थानीय क्षमता निर्माण के नए अवसर भी सृजित करेगी।

उप राज्यपाल ने अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित रानी लक्ष्मीबाई शिला, जिसे पहले फ्लैट रॉक/इनविज़िबिल बैंक के नाम से भी जाना जाता था, व जिसका आपने एरियल निरीक्षण भी किया था, पर लाइट हाउस का निर्माण, नेविगेशनल की स्थापना तथा विदेश मंत्रालय द्वारा भारत की नेशनल बेसलाइन का पुनर्निर्धारण व नोटिफिकेशन सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। यह उपलब्धि न केवल भारत की समुद्री महत्ता को सुदृढ़ करती है, बल्कि भारत–प्रशांत क्षेत्र में हमारे सामरिक संभावना को भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती है। उप राज्यपाल ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन व्यापक दृष्टि के अनुरूप, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प में अपनी पूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने माननीय गृह मंत्री के समर्थन के लिए द्वीप प्रशासन की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की और यह आश्वस्त कराया है कि इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चन्द्र भूषण कुमार (भा.प्र.से.) के धन्यवाद ज्ञापन से समारोह सम्पन्न हुआ। (स्रोत : प.सू.का. एवं संवाददाता की रिपोर्ट)

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गृह मंत्रालय की संसदीय

पृष्ठ 1 का शेष

फॉरेंसिक क्षमताओं में बढ़ोतरी और विस्तार के लिए भारत सरकार ने 2020 से ही फॉरेंसिक्स पर फ़ोकस करके काम किया। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिताएं जुलाई, 2024 से लागू हुईं, परंतु हमने फॉरेंसिक्स की दृष्टि से इसे लागू करने का काम 2020 से ही शुरू कर दिया था, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून आने के बाद जांच में तेजी और सजा की दर बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक बच्ची से बलात्कार के दोषी को 62 दिनों में फांसी की सजा सुना दी गई। बिहार के सीवान ज़िले में ट्रिपल मर्डर की घटना में सिर्फ 50 दिन में दो दोषियों को सजा सुनाई गई। श्री शाह ने कहा कि इन मामलों से साबित होता है कि हमें सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि पहले हमारे सामने 5 चुनौतियाँ थीं, जिनमें फॉरेंसिक जांच में टेक्नॉलजी संबंधी बड़ा गैप, चेन ऑफ कस्टडी के कारण साक्ष्य की गुणवत्ता का सीमित होना, कई जगहों पर पुलिस द्वारा फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट अदालत में नहीं देना, स्किल्ड प्रोफेशनल्स और फॉरेंसिक लैब्स की कमी और राष्ट्रव्यापी मापदंडों की कमी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून के प्रावधानों के मुताबिक अब फॉरेंसिक लैब अपनी रिपोर्ट सीधा अदालत को भेजेगी और उसकी एक प्रति पुलिस को देगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकारें देश भर में फॉरेंसिक लैब्स का जाल बुनने के लिए अगले पाँच साल में 30 हजार करोड़ रुपए निवेश करने वाली हैं। साथ ही, राष्ट्रव्यापी मापदंडों की कमी को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक तंत्र तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम प्रथाओं और कमियों को साझा कर एक राष्ट्रव्यापी मापदंड निर्धारित किया जाएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमने वैज्ञानिक सुधार, सुरक्षित डेटाबेस का विकास, तकनीक और मानव संसाधन क्षमता निर्माण, संस्थाओं का सशक्तिकरण और केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में टेक्नॉलजी को महत्व दिया गया है। ई–समन और ई–साक्ष्य जैसे सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाँच स्तंभों यानि पुलिस, कोर्ट, जेल, फॉरेंसिक और प्रोसिक्यूशन का पूर्ण आधुनिकीकरण करके डाटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सहेजने, डाटा के एक–दूसरे से संवाद और एआई के आधार पर इनके सतत विश्लेषण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक विज़िट अनिवार्य कर दी गई है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि हमने चैन ऑफ कस्टडी को सर्कुलर नहीं, बल्कि न्यायिक दृष्टि से मजबूत किया है। जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है, ताकि पुलिस पर कोई गलत आरोप नहीं लग सके। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों को निर्णायक रूप से कानूनी आधार देकर प्रमाण के रूप में प्रस्थापित करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध, संगठित अपराध, आतंकवाद और डिजिटल धोखाधड़ी पहले परिभाषित नहीं था, लेकिन हमने इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर अदालतों के लिए ग्रे एरिया को कम किया है। ट्रायल इन एबसेंटिया पर अमल से देश छोड़ कर भाग जाने की प्रवृति पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों को भी नए आपराधिक कानूनों में प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि ई–एफआईआर और ज़ीरो एफआईआर गरीबों और महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है।

श्री अमित शाह ने कहा कि नवंबर, 2025 तक देश के हर पुलिस स्टेशन को (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) पर ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज हर एफआईआर सेंट्रल सर्वर पर उपलब्ध है। अपराध की मैपिंग के लिए आने वाले दिनों में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया जाने वाला है। लगभग 36 करोड़ लेगेसी डाटा के साथ 7 लाख एफआईआर का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है। 22 हजार कोर्टस को ई–कोर्टस से जोड़ा गया है। ई–प्रिजंस में देश भर की जेलों के 2 करोड़ 20 लाख कैदियों का डाटा सेंट्रल सर्वर में उपलब्ध है। ई–प्रोसिक्यूशन में लगभग 2 करोड़ प्रोसिक्यूशन का डाटा उपलब्ध है। नए प्रोसिक्यूशन में सभी की जानकारी ई–प्रोसिक्यूशन में उपलब्ध हो रही है। 30 लाख 54000 मामलों का डाटा ई–फॉरेंसिक्स पर उपलब्ध है, ताकि पुलिस इसका उपयोग कर सके। नेशनल ऑटोमेटड फिंगरप्रिंट आइडिंटिफिकेशन सिस्टम (एनएएफआईएस) पर एक करोड़ 21 लाख फिंगर प्रिन्ट उपलब्ध हैं, जिससे पुलिस को मामलों की जांच में मदद मिल रही है। 9 लाख 44 हजार नार्को अपराधियों का डाटा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। मानव तस्करी में लिप्त 3 लाख 65 हजार अपराधियों का डाटा ऑनलाइन हो चुका है। उन्होंने कहा कि गैर–कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज़ होने वाले आतंकवाद के सभी मामलों का डाटा भी एनआईए के डेटाबेस में अलग से दर्ज़ किया जा रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि अभी देश में 7 सीएफएसएल हैं, जबकि 8 नए सीएफएसएल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ऐसा नहीं रहेगा जहां एनएफएसयू या सीएफएसएल में से कोई एक संस्था नहीं हो। उन्होंने कहा कि राज्यों की एफएसएल, फॉरेंसिक वैन और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को मज़बूत करने के लिए हमने लगभग 1 हज़ार करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री शाह ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस विभागों के मानकीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ई–फॉरेंसिक्स के आईटी प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत हो गई है और सीएफएसएल सहित 143 देश की प्रयोगशालाएं इससे जुड़ चुकी है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2029 तक एनएफएसयू में फॉरेंसिक के 35 हज़ार छात्र पढ़ रहे होंगे और 3–4 साल में हम सेचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनएफएसयू में शत प्रतिशत प्लेसमेंट होता है। गृह मंत्री ने कहा कि अब तक एनएफएसयू के 14 कैंपस बन चुके हैं और यह यूनिवर्सिटी 100 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में लगभग 16 हज़ार से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम किया है और इस संख्या को अगले 4 साल में लगभग तीन गुना तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनएफएसयू ने अब तक 46 पेटेंट रजिस्टर्ड किए हैं, जिनमें से 30 सिर्फ 2024 में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 96 देशों ने एनएफएसयू के साथ 103 एमओयू किए हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों के 117 संगठनों ने भी एनएफएसयू के साथ समझौते किए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि लॉंग टर्म रोडमैप में एकीकृत फॉरेंसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम हाथ में लिया गया है और हम इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले समय में फ़ोरेंसिक इंटेलीजेंस में भी हम अच्छा काम करेंगे। इसके साथ ही फ़ॉरेंसिक के नतीज़ों का एआई–बेस्ड एनिलिसिस और सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करने का काम भी किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि तीन नए आपराधिक क़ानूनों के लागू होने के बाद जल्द परिणाम लाने के प्रयासों के अच्छे प्राथमिक नतीजे मिल रहे हैं। (स्रोत : प.सू.का.)

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने प्रदर्शनी मैदान में

पृष्ठ 1 का शेष

मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अधिनियमन एवं क्रियान्वयन भारत में एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी–सक्षम तथा नागरिक–केंद्रित आपराधिक न्याय प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। संस्थागत सहयोगों और डिजिटल नवाचारों से समर्थित ये नए कानून औपनिवेशिक कालीन कानूनी ढांचे का स्थान लेते हुए त्वरित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी न्याय सुनिश्चित करते हैं।

श्री अमित शाह ने अपील की कि आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े प्रत्येक हितधारक के साथ–साथ आम जनता को भी इस प्रदर्शनी का अवश्य अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यह न्याय वितरण प्रणाली में लाए जा रहे दूरगामी परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। उन्होंने बताया कि नई न्याय संहिता का उद्देश्य निर्धारित समय–सीमा के भीतर न्याय सुनिश्चित करना है।

इस प्रदर्शनी का उद्देश्य नए कानूनों के प्रति जागरूकता पैदा करना है, जिन्हें दंड से न्याय की ओर आपराधिक न्याय प्रणाली के फोकस को स्थानांतरित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, साथ ही अपराध के प्रति निवारक प्रभाव भी सुनिश्चित किया गया है।

ई–एफआईआर, ज़ीरो एफआईआर, तलाशी एवं ज़ब्ती की अनिवार्य वीडियोग्राफी तथा गंभीर अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच जैसे प्रावधानों को जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और नागरिक–केंद्रित बनाने के लिए शामिल किया गया है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए एक पृथक अध्याय भी जोड़ा गया है, जो उनकी सुरक्षा और गरिमा के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

न्याय संहिता एक परिवर्तनकारी सुधार है और पूर्ववर्ती आपराधिक कानूनों से एक मौलिक परिवर्तन का प्रतीक है। पूर्व कानून जटिल थे, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी थी, पीड़ित के प्रति उदासीन थे और उनमें औपनिवेशिक दमनकारी विरासत विद्यमान थी। नए कानून सूचना प्रौद्योगिकी, फॉरेंसिक एवं अन्य वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय प्रणाली प्रदान करने पर आधारित हैं। न्याय संहिता पीड़ित–केंद्रित, समयबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सरल है, जिसमें जांच, साक्ष्य संग्रहण एवं उनके डिजिटलीकरण में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया गया है।

प्रदर्शनी मैदान में आयोजित तीन दिवसीय यह प्रदर्शनी नागरिकों और हितधारकों के बीच भारत की नई आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत लाए गए परिवर्तनकारी सुधारों के प्रति जागरूकता पैदा करने का लक्ष्य रखती है, जो पहले मुख्य रूप से दंड पर केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर न्याय की ओर बढ़ने की दर्शनशास्त्र पर आधारित है।

प्रदर्शनी मैदान में आयोजित न्याय संहिता पर यह प्रदर्शनी, जो अब आम जनता के लिए खुली है, सूचना के साथ–साथ वास्तविक समय की परिस्थितियों और अपराध स्थलों, पुलिस थानों, जेलों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालयों आदि के दृश्य सृजन का समन्वय प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं तथा आम जनता की बेहतर समझ के लिए नए कानूनों के महत्व और परिवर्तनकारी पहलुओं को नाटिकाओं एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। न्याय संहिता पर प्रदर्शनों के अतिरिक्त, प्रशासन द्वारा कृषि, आपदा प्रबंधन एवं पर्यटन विभागों की पहलों को भी प्रदर्शित किया गया है, जो अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की परिवर्तनकारी विकास यात्रा तथा सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति को दर्शाती हैं।

प्रदर्शिनी मैदान, श्री विजय पुरम में आयोजित यह प्रदर्शनी 4 से 6 जनवरी, 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10.30 बजे से सायं 5.15 बजे तक आम जनता तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए खुली रहेगी और यह न्याय संहिता तथा समाज एवं व्यक्तियों पर उसके प्रभाव के संबंध में रोचक एवं संवादात्मक प्रारूप में जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होने की अपेक्षा है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय, श्री विजय पुरम

प्रेस विज्ञप्ति

F.No. 4-13/2025 - R & E Cell/494 दिनांक 31.12.2025

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के दिनांक 06.11.2025 के रिक्ति सूचना 4–12/2025/आर एंड ई सेल/382 के संदर्भ में संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों/आवेदकों को सूचित किया जाता है कि पदों से संबंधित पाठ्यक्रम दिनांक 02.01.2026 से संबंधित पोर्टल https://erecruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

ह./–
(एम. वी. रमेशन)
उप सचिव (भर्ती एवं परीक्षा)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय, श्री विजय पुरम

प्रेस विज्ञप्ति

F.No. 4-13/2025 - R & E Cell/492 दिनांक 31.12.2025

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के दिनांक 06.11.2025 के रिक्ति सूचना संख्या : 4–12/2025–आर एंड ई सेल/382 के संदर्भ में, संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा के लिए दिनांक 07.01.2026 के प्रातः 11.00 बजे से लेकर 13.01.2026 (रात्रि 12.00 बजे तक) एक सुधार विंडो खोली जा रही है, जिससे आवेदक द्वारा की गई, यदि कोई त्रुटि हो, तो अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं।

इस प्रकार आवेदक वेबसाइट के पोर्टल https://erecruitment.andamannicobar.gov.in में जाकर, यदि कोई त्रुटि हो तो, सुधार कर सकते हैं।

वेबसाइट पर उपलब्ध उम्मीदवारों का आवेदन से संबंधित विवरण अंतिम तिथि, अर्थात 13.01.2026 के मध्य रात्रि के उपरान्त अंतिम माना जाएगा। अतः उम्मीदवारों के हित में सलाह दी जाती है कि ऊपरनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक उचित सुधार करें।

ह./–
(एम. वी. रमेशन)
उप सचिव (भर्ती एवं परीक्षा)

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रमुख, पंचायत समिति, प्रात्रापुर की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2025–26/175
कार्य का नाम : प्रात्रापुर समिति द्वारा, टेलराबाद वार्ड न. 03 में रामास्वामी के घर से पुजारी के घर तक ग्रामीण सड़क की मरम्मत और रखरखाव।
अनुमानित लागत : 3. 7,92,642/–, धरोहर राशि : रु. 15,853/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (03) तीन माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 12/01/2026 के सायं 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_21300_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

मत्स्य पालन विभाग का नीली क्रांति में स्वदेशी पर बल

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

हिमालयी नदियों से लेकर हिंद महासागर के तटीय जल तक फैले भारत के विविध जलीय इको–सिस्टम में स्वदेशी मछली प्रजातियों का भंडार है। यह देश के पारिस्थितिक संतुलन और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। इन स्वदेशी प्रजातियों का संवर्धन न केवल मत्स्य पालन की स्थिरता के लिए बल्कि खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। देश में मछली उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के प्रयासों के बीच, देशी मछली प्रजातियों का रणनीतिक संवर्धन देश की समृद्ध जलीय विरासत को संरक्षित करते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

स्थानीय या देशी प्रजातियां वे हैं जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों और जलीय वातावरणों के अनुकूल विकसित और अनुकूलित हुई हैं। भारत में, इन प्रजातियों में मीठे पानी, खारे पानी और समुद्री मछलियों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। इनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी पारिस्थितिक भूमिका और आर्थिक महत्व है। 2800 से अधिक स्थानीय मछली और शंख प्रजातियों की पहचान की गई है। इनमें से 917 प्रजातियाँ मीठे पानी से, 394 प्रजातियां खारे पानी से और 1548 प्रजातियां समुद्री हैं (स्रोतः आईसीएआर–एनबीएफजीआर)।

इन वर्षों में देश ने व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 80 से अधिक मछली/शंख प्रजातियों के लिए प्रजनन और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। हालांकि, देश के मत्स्य पालन उत्पादन में मुख्य योगदान कुछ चुनिंदा प्रजातियों का ही है।

भारत की चौथी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4* का समुद्री परीक्षण शुरू

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

भारत की चौथी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4* का समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है। 7000 टन वजन वाली यह पनडुब्बी पिछले सप्ताह विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित शिपबिल्डिंग सेंटर (एसबीसी) से समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुई। S4* (चार सितारा) अरिहंत श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी है और इसमें 3500 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली आठ परमाणु–युक्त के–4 पनडुब्बी–प्रवेशित बैलिस्टिक मिसाइलें (एसएलबीएम) हैं।

S4* पनडुब्बी के 80 प्रतिशत से अधिक उपकरण स्वदेशी घटकों से निर्मित हैं, जो चारों इकाइयों में सबसे अधिक है। पनडुब्बी का परीक्षण एक वर्ष तक चलने की उम्मीद है, जिसके बाद यह 2027 की शुरुआत तक सेवा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगी।

भारत के पास अब समुद्र में चार एसएसबीएन हैं, जिनमें से दो सेवा में हैं और दो परीक्षण के अधीन हैं। तीसरा एसएसबीएन, आईएनएस अरिधमन, अपने समुद्री परीक्षण पूरे कर चुका है और 2026 के अंत में कमीशन होने के लिए तैयार है। यह रणनीतिक उपलब्धि उस परियोजना की परिणति है जो 1984 में तीन एसएसबीएन की आपूर्ति के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (एटीवी) परियोजना की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। एस4' को एक दशक से भी पहले एस4 और बड़ी एस5 एसएसबीएन परियोजना के बीच एक अंतरिम समाधान के रूप में ऑर्डर किया गया था।

आईएनएस अरिहंत का सफर 1998 में शुरू हुआ, जब इसके ढांचे का काम शुरू हुआ। यह वही समय था जब भारत ने पोखरण में अपने परमाणु परीक्षणों से दुनिया को चौंका दिया था। इसके बाद, 2009 में इसे पानी में उतारा गया और 2016 में यह भारतीय नौसेना का हिस्सा बनी। 2018 में, इसने सफलतापूर्वक अपना पहला निवारक गश्ती अभियान पूरा किया, जिसका मतलब है कि यह समुद्र में तैनात होकर दुश्मन पर नजर रखने और किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार थी। अब, आईएनएस अरिघात के शामिल होने से भारत की पनडुब्बी बेड़ा और भी मजबूत हो गया है।

स्वास्थ्य सुरक्षा में बड़ा कदमः भारत एआई की मदद से महामारी का पूर्वानुमान कर पहले ही जारी करेगा अलर्ट

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

भारत अब बीमारी फैलने का इंतज़ार नहीं करेगा। सरकार एक ऐसा नया सिस्टम तैयार कर रही है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़े डाटा का उपयोग करके बीमारी का अंदाज़ा पहले ही लगा सकेगा। इससे डेंगू, चिकनगुनिया, लू जैसी बीमारियों के बढ़ने की चेतावनी समय रहते मिल जाएगी और इससे निपटने की तैयारी समय रहते की जा सकेगी।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के निदेशक डॉ रंजन दास ने बताया कि देश की पुरानी प्रणाली, जिसमें बीमारी फैलने के बाद कार्रवाई होती थी, वह अब बदल रही है। नई व्यवस्था में बीमारी शुरू होने से पहले ही उसका संकेत मिल जाएगा। इससे तेजी से फैसले लेने और बीमारी को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। नए मॉडल की खास बात यह है कि अलर्ट मिलते ही ज़मीन पर काम करने वाली टीमें भी तुरंत सक्रिय हो जाती हैं।

वहीं एनसीडीसी के अतिरिक्त निदेशक डॉ हिमांशु चौहान ने कहा कि एआई के जरिए अभी ऐसा एक सिस्टम बना है जो इंटरनेट पर रोजाना 13 भाषाओं में लाखों खबरें और पोस्ट पढ़ता है। यह सिस्टम अपने आप पहचान लेता है कि कहां कौन–सी बीमारी में अचानक बढ़ोतरी हो रही है, किस इलाके में किस तरह का खतरा हो सकता है और किस जानकारी को अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाना है।

अब तक यह सिस्टम 300 मिलियन (30 करोड़) से ज्यादा ऑनलाइन खबरें स्कैन कर चुका है और 95,000 से ज्यादा स्वास्थ्य घटनाओं का पता लगा चुका है। इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को इंसानी टीम के लिए जांचना मुश्किल था। अब एआई ने यह काम लगभग 98% आसान कर दिया है। यह सिस्टम एक तरह से डिजिटल चौकीदार की तरह काम करता है और बीमारी से जुड़े असामान्य संकेतों को पकड़कर तुरंत अलर्ट जारी करता है।

अधिकारियों ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि भारत एक ऐसा पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाए जो आने वाली महामारी, जलवायु से जुड़ी बीमारियों और नए संक्रमणों का पहले से मुकाबला कर सके। डॉ रंजन दास के मुताबिक, हम पहले बीमारी फैलने का इंतजार करते थे, अब पहले से अंदाजा लगाकर तैयारी करेंगे। भारत की रोग निगरानी अब डाटा–ड्रिवन, स्मार्ट और प्रीडिक्टिव हो रही है।

डॉ हिमांशु ने बताया कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो पुराने और ताज़ा डेटा को जोड़कर यह अनुमान लगाती है कि भविष्य में बीमारी कहां और कब बढ़ सकती है। इसमें मौसम, जनसंख्या, माइग्रेशन, लैब रिपोर्ट, अस्पतालों के केस, पशु–पक्षी संक्रमण सबका डाटा शामिल होता है। इससे अचानक फैलने वाली बीमारियों (आउटब्रेक) को पहले ही पहचान कर काबू किया जा सकता है।

निवेशकों के लिए सेबी ने सुधारों की घोषणा की

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

निवेशकों के लिए नियमों के अनुपालन को आसान बनाने और बाज़ार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाए गए एक कदम में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड–सेबी ने बुधवार को डुप्लिकेट प्रतिभूतियां जारी करने और बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट. बी.एस.डी.ए फ्रेमवर्क से जुड़े सुधारों की घोषणा की।

डुप्लीकेट प्रतिभूतियां जारी करने की प्रक्रिया को तेज़, ज़्यादा कुशल और निवेशक–अनुकूल बनाने के लिए, सेबी ने आसान दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के लिए मौद्रिक सीमा को पहले के 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। संशोधित नियमों के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशकों को अब कम दस्तावेज जमा करने होंगे। इससे विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा और प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम किया जा सकेगा।

सेबी ने बी.एस.डी.ए पात्रता तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाली वैल्यूएशन सीमा से ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल. जेड.सी.जेड.पी. बॉन्ड और डीलिस्टेड प्रतिभूतियों को हटाकर बी.एस.डी.ए नियमों में भी ढील दी है। नियामक ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य बी.एस.डी.ए सुविधा को और बेहतर बनाना, निवेशकों के लिए निवेश को आसान बनाना और जमाकर्ता प्रतिभागी के लिए अनुपालन का बोझ कम करना

आर्मी हॉस्पिटल ने भारत में आईस्टेंट के साथ पहली 3डी फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

भारतीय चिकित्सा जगत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) के नेत्र विज्ञान विभाग ने भारत में पहली बार आईस्टेंट के साथ 3डी फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक संपन्न की है। यह एंजियोग्राफी उन्नत इमेजिंग तकनीक और न्यूनतम चीर–फाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी को मिलाकर की गई।

नए स्टैंड–माउंटेड स्पेक्ट्रालिस सिस्टम और अत्याधुनिक 3डी ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से की गई इस प्रक्रिया ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं को वैश्विक नेत्र चिकित्सा के अग्रिम पंक्ति में स्थापित किया है।

ग्लूकोमा, जो अपरिवर्तनीय अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक है, अपनी धीमी प्रगति के कारण लंबे समय से चिकित्सकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यह तकनीक एक्वियस आउटफ्लो पाथवे का वास्तविक समय और अत्यंत सटीक दृश्य उपलब्ध कराती है, जिससे सर्जन अधिक लक्षित और प्रभावी उपचार कर सकते हैं व रोगियों के परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार संभव हो पाता है।

देश में पहली बार 3डी फ्लेक्स एक्वियस एंजियोग्राफी को आईस्टेंट (न्यूनतम इनवेसिव ग्लूकोमा सर्जरी) के साथ एकीकृत कर ग्लूकोमा उपचार में एक नया मानदंड स्थापित किया गया है। इससे सर्जरी के दौरान बेहतर इमेजिंग और दीर्घकालिक रूप से बेहतर परिणाम सुनिश्चित होते हैं। सशस्त्र बल समुदाय के लिए यह उपलब्धि न सिर्फ एक महत्वपूर्ण चिकित्सा मील का पत्थर है, बल्कि दृष्टि संरक्षण और ऑपरेशनल तत्परता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम भी है।

बर्फ, तूफान और –30 डिग्री तापमान, साउथ पोल पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी काम्या कार्तिकेयन

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

नौसेना ने मंगलवार को बताया कि भीषण ठंड और तेज हवाओं का सामना करते हुए एक नौसैन्य अधिकारी की 18 वर्षीय बेटी ने स्कीइंग करते हुए दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनने का गौरव हासिल किया है। भारतीय नौसेना ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में काम्या कार्तिकेयन को बधाई दी।

नौसेना ने कहा, ''काम्या ने शून्य से –30 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान और तूफानी हवाओं का सामना करते हुए, 89 डिग्री दक्षिण से लगभग 60 समुद्री मील (लगभग 115 किमी) की दूरी तय की, जिसमें वह अपने पूरे अभियान के सामान से लदी एक स्लेज को खींच रही थीं, और 27 दिसंबर 2025 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचीं।'' नौसेना ने उसके द्वारा स्लेज खींचे जाने का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।

पोस्ट में कहा गया, ''भारतीय नौसेना एक नौसैन्य अधिकारी की 18 वर्षीय बेटी एवं नेवी चिल्ड्रन स्कूल की पूर्व छात्रा काम्या कार्तिकेयन को बधाई देती है, जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनकर एक बार फिर इतिहास रच दिया है।''

नौसेना के अनुसार, पर्वतारोहण में विलक्षण प्रतिभा की धनी काम्या का लक्ष्य 'एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम' को पूरा करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनने का है – यह एक ऐसा साहसिक कार्य है जिसमें सभी सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना और दोनों ध्रुवों तक स्कीइंग करना शामिल है। इससे पहले, वह माउंट एवरेस्ट सहित सातों शीर्ष पर्वत चोटियों तक पहुंचने की चुनौती को पूरा कर चुकी हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल होंगे कप्तान, मोहम्मद शमी को मौका नहीं

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। सीनियर पुरुष चयन समिति ने वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है। यह सीरीज 11 जनवरी से 18 जनवरी तक भारत में खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत बड़ौदा से होगी।

इस सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है। पहला वनडे बड़ौदा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। चयनकर्ताओं ने इस दौरे के लिए युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलित संयोजन तैयार किया है।

हार्दिक पांड्या को इस वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन्हें एक मैच में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी की मंजूरी नहीं दी है। साथ ही आगामी आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उनके वर्कलोड का विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। इसके अलावा मोहम्मद शमी, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को भी टीम में जगह नहीं मिल सकी है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है।

टीम में यशस्वी जायसवाल, नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, वहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम की रीढ़ बने रहेंगे। चयन समिति का फोकस आने वाले बड़े टूर्नामेंटों को देखते हुए खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म पर रहा है।

भारत की वनडे टीमः– शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)', वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

सरकार ने पी.एल.आई. योजना के तहत नए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ायी

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन –पी.एल.आई. योजना के तहत नए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है।

वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि ऐसा पिछले वर्ष अगस्त में आवेदन पोर्टल के फिर से खुलने के बाद से वस्त्र कंपनियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के मद्देनजर किया गया है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह निर्णय देश के वस्त्र क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है। इसका लक्ष्य पात्र आवेदकों को अतिरिक्त समय देकर व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

इतिहास के पन्नों में 04 जनवरी

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

2020 – केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नयी दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। यह नयी दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का 28वां संस्करण है, इसकी थीम 'गांधीः लेखकों के लेखक' रखी गयी।
2010– भारत में 'स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' के आदेश पर शेयर बाज़ारों के खुलने का समय एक घंटा पहले सुबह 9 बजे कर दिया गया।
2009– पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यूपीए से नाता तोड़ा।
2008 – अमेरिका ने श्रीलंका को सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगायी।
2006 – दुबई के शासक शेख़मकतूम बिन रशीद अल मकतूम का निधन।
2004 – भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाक प्रधानमंत्री जमाली के बीच इस्लामाबाद में वार्ता।
2002 – ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भारत पहुँचे।
1999 – मंगल ग्रह पर भाप का विश्लेषण करने हेतु अमेरिकी यान 'मार्स पौसर लैंडर प्रोब' का प्रस्थान।
1998 – बांग्लादेश ने भारत को उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को सौंपने से इनकार किया।
1990 – पाकिस्तान में दो ट्रेनों की टक्कर में करीब 307 लोग मारे गए और उससे दोगुने घायल हुए।
1972 – नई दिल्ली में 'इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनालॉजी एंड फारेंसिक साइंस' का उद्घाटन।
1966 – भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच भारत–पाकिस्तान सम्मलेन की शुरूआत।

चुनाव आयोग ने नागरिकों से मांगे 'इसीआईनेट' को बेहतर बनाने के सुझाव

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

भारत निर्वाचन आयोग सभी नागरिकों को ईसीआईनेट ऐप डाउनलोड करने और ऐप में मौजूद 'सुझाव प्रस्तुत करें' टैब का उपयोग कर ऐप को बेहतर बनाने की दिशा में अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित करता है। नागरिक 10 जनवरी, 2026 तक अपने सुझाव दे सकते हैं।

नए ईसीआईएनईटी ऐप के प्रयोगत्मक प्रारूपों से मतदाताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, मतदान प्रतिशत के रुझान तेजी से उपलब्ध होंगे और मतदान समाप्त होने के 72 घंटों के भीतर इंडेक्स कार्ड प्रकाशित किए जा सकेंगे, जो प्रक्रिया पहले कई हफ्तों या महीनों में पूरी हो जाती थी। इस ऐप का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उपचुनावों के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

सीईओ, डीईओ, ईआरओ, ऑब्जर्वर और फील्ड अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर और परिष्कृत किया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं के सुझावों की जांच की जाएगी और प्लेटफॉर्म को और अधिक उपयोगकर्ता–अनुकूल बनाने के लिए अपडेट किया जाएगा। ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म को इस महीने आधिकारिक तौर पर शुरू किया जाएगा।

ईसीआईनेट, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ शुरू की गई आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है। ईसीआईनेट ऐप के विकास पर काम 4 मई, 2025 को इसकी घोषणा के बाद शुरू हुआ।

ईसीआईनेट ऐप नागरिकों के लिए एक एकीकृत ऐप है जो पहले से मौजूद 40 अलग–अलग चुनाव संबंधी एप्लिकेशन/वेबसाइटों जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए), सीविजिल, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स (मतदाता मतदान ऐप), नो योर कैंडिडेट (केवाईसी) ऐप को एक ही इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है।

जेन जी और जेन अल्फा 2047 तक देश को बनाएंगे 'विकसित भारत'–केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा ही 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त कर 2047 तक देश को विश्व गुरु बनाएंगे। साथ ही युवा शक्ति की अथक मेहनत से भारत 2047 तक 25 ट्रिलियन आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। ये शताब्दी भारत की शताब्दी होने वाली है। शनिवार को केन्द्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव आकाशवाणी भवन के सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशती और श्रीकांत जोशी की स्मृति में मदरलैंड इंटरनेशनल फाउंडेशन एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित ''पंच परिवर्तन'' संगोष्ठी में बोल रहे थे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार, मदरलैंड इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. एके अग्रवाल, सुरेश चौहान, शाहिद अख्तर, श्रीराम जोशी मौजूद रहे।

सभा को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पंच परिवर्तन विचार ने पांच हजार साल पहले भारत विश्व गुरु रहा। दो हजार साल पहले भारत सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। भारत ने विश्व को गिनती सिखाई, दशमल्व दिया। सदियों से विश्व को दिशा देने वाला राष्ट्र भारत रहा। लेकिन बीच में कुछ दशकों तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाए रखा, हमारे निर्माण क्षमता को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब वो देश करवट ले रहा है। आज भारत विश्व में पांचवी आर्थिक ताक़त से चौथे स्थान पर आ गया है।

उन्होंने कहा कि 11 साल देश में ६६ प्रतिशत मोबाइल फ़ोन देश के बाहर से आयात होते थे लेकिन आज परिस्थितियां बदली है। आज देश ६६ प्रतिशत फ़ोन भारत में बनते है और निर्यात होते हैं। दुनिया के कई देश आज वंदे भारत ट्रेन में दिलचस्प ले रहे हैं।वंदे भारत स्लीपर या रॉकेट हो या सेमी कंडक्टर चिप्स हो इन सब में देश के

नागरिक की सोच छपी है। उन्होंने कहा कि पंच परिवर्तन में पर्यावरण अहम भाग रहा है। देश ने हमेशा पर्यावरण को सहेजा है। यह लोगों के घरों में तुलसी के पौधे के रूप देख सकते हैं।

इस अवसर पर आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। लेकिन हम अपनी खोई हुई भूमि की तरफ़ तो जा सकते हैं। जो ख़त्म होना चाहता है उसका उत्तर खोज कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंच परिवर्तन से समाज बदलेगा। किसी भी दूसरे देश में हिम्मत नहीं है जो खुद को विश्व गुरु कहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा दुनिया में कहीं और सुनाई नहीं देता है। पंच परिवर्तन के नियमों से हम विश्व गुरु बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्नता में एकता वाला देश है। यही इसकी सुंदरता है। इसलिए दुनिया की एकता का बेमिसाल उदाहरण है भारत। हम जीना जानते है और सबक सिखाना भी जानते हैं। इस अवसर पर मदरलैंड इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. एके अग्रवाल ने पंच परिवर्तन संगोष्ठी की प्रस्तावना रखी और सभी से इसका स्मरण करने का आह्वान किया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 'बदलता भारत मेरा अनुभव' अभियान के विजेताओं की घोषणा की

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 'बदलता भारत मेरा अनुभव' अभियान के तहत चार रचनात्मक चुनौतियों के विजेताओं की घोषणा की है। यह चुनौतियाँ माइगोव (MyGov) प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित की गई थीं। इस अभियान के अंतर्गत नागरिकों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में हुए बदलावों को दर्शाने वाले अपने व्यक्तिगत अनुभव और क्रिएटिव विचारों को शेयर करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप, इस अभियान में सभी लोगों ने उत्साह से हिस्सा लिया। इंद्रजीत सुबोध मशांकर को 'बदलता भारत मेरा अनुभव– इंस्टाग्राम रील प्रतियोगिता' श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है, जबकि मंथन रोहित को 'बदलता भारत मेरा अनुभव– यूट्यूब शॉर्ट्स चैलेंज' श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है। इसके अलावा, 'शॉर्ट ऑडियो–विजुअल चैलेंज में नए भारत की

कहानी' श्रेणी में सुशोवन मन्ना ने पहला पुरस्कार जीता, जबकि कृष्णा गुप्ता ने 'बदलता भारत मेरा अनुभव– ब्लॉग लेखन प्रतियोगिता' श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 'बदलता भारत मेरा अनुभव' अभियान के विजेताओं और प्रतिभागियों को विकसित भारत की कहानियों को बताने में उनके उत्साहपूर्ण योगदान के लिए बधाई दी है।

एनसीसी के एक लाख कैडेट को मिलेगा प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सबसे पहले देंगे प्रतिक्रिया

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने शनिवार को कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित सहायता के लिए एक लाख कैडेट को प्रशिक्षित करने की योजना बना बनाई जा रही है। दिल्ली कैंट में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वत्स ने कहा कि इन कैडेट को 'युवा आपदा मित्र' के रूप में जाना जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय डाटाबेस से जोड़ा जाएगा, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर देश उनकी सेवाओं का उपयोग कर सके।

उन्होंने बताया कि एनसीसी ने देशभर में चार से पांच केंद्र स्थापित करने पर भी काम शुरू कर दिया है, जहां चयनित कैडेट को ड्रोन और 'काउंटर–ड्रोन' से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, 10,000 कैडेट को 'साइबर योद्धा' के रूप में तैयार करने की योजना पर भी काम जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल वत्स ने कहा, "ये कैडेट डिजिटल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आज साइबर क्षेत्र का तेजी से सैन्यकरण हो रहा है।"

उन्होंने बताया कि इन्हें भी राष्ट्रीय डाटाबेस से जोड़ा जाएगा। वत्स ने यह घोषणा भी की कि एनसीसी के इतिहास में वर्ष 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में इसके परेड और दल कमांडर तलवार लेकर मार्च करेंगे। देशभर से 898 बालिकाओं समेत कुल 2,406 एनसीसी कैडेट गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में भाग ले रहे हैं। यह शिविर 30 दिसंबर से दिल्ली कैंट में स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड में शुरू हुआ है।

हैम रेडियो से गंगासागर में नई डिजिटल क्रांति, सुरक्षित संचार से बढ़ेगी यात्रियों की सुरक्षा

कोलकाता, 03 जनवरी।

गंगासागर मेले में इस बार हैम रेडियो के जरिए नई डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सुरक्षित और तेज संचार संभव हो सकेगा। इस नई व्यवस्था का मकसद संदेशों को सुरक्षित रखना और यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करना है। हैम रेडियो के माध्यम से अब देश के किसी भी हिस्से में कुछ ही पलों में सुरक्षित संदेश भेजे जा सकेंगे।

अब तक वेस्ट बंगाल रेडियो क्लब के हैम रेडियो ऑपरेटर जिला प्रशासन के अनुरोध पर गंगासागर मेले में एनालॉग रेडियो के जरिए सेवाएं देते रहे हैं। मेले के दौरान खोए हुए लोगों की जानकारी पहुंचाने से लेकर गंभीर रूप से बीमार तीर्थयात्रियों को बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से कोलकाता के विभिन्न सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में भेजने तक, हैम रेडियो ने अहम भूमिका निभाई है। कई बार ऐसे मरीजों के परिजनों का पता न होने की स्थिति में भी हैम रेडियो के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में सूचना पहुंचाई गई है। नई डिजिटल तकनीक के आने से यह काम और तेज तथा प्रभावी होने की उम्मीद है।

बताया गया है कि अब संदेश सीधे देशभर के हैम रेडियो ऑपरेटरों तक तुरंत पहुंच सकेंगे, जिससे परिणाम भी जल्दी मिलेंगे। पिछले 36 वर्षों से हैम रेडियो ऑपरेटर अस्थायी कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे देश में संदेश भेजते आ रहे हैं। इस बार मेले के भौगोलिक बदलाव और भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए कंट्रोल रूम पर दबाव अधिक रहने की आशंका है। साथ ही, इस बार कुंभ मेले

के न होने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के गंगासागर आने की संभावना जताई जा रही है।

गंगासागर मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी यह तकनीक अहम मानी जा रही है। रेडियो सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की ओर से गंगासागर द्वीप को एएस 153 के रूप में मान्यता मिली है। इससे विश्व मानचित्र पर गंगासागर द्वीप की भौगोलिक स्थिति को खास महत्व मिला है। इसका असर यह हुआ है कि साल भर विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक सागर आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के आर्थिक विकास की उम्मीद भी बढ़ी है। मेले के दौरान विदेशी पर्यटक भी लगातार जानकारी चाहते हैं, ऐसे में रेडियो के जरिए उन्हें लाइव अपडेट मिल सकेगा। आपदा की स्थिति में भी यह संचार व्यवस्था बेहद उपयोगी साबित होगी।

ग्राहक अनुभव के लिए तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को मिला 'लेवल–3' प्रमाणन

तिरुवनंतपुरम, 03 जनवरी।

तिरुवनंतपुरम स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों के बेहतर अनुभव के लिए 'अंतरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र परिषद' (एसीआई) की प्रतिष्ठित 'लेवल–3' मान्यता प्रदान की गई है। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआरवी) द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, उसकी इस मान्यता को 'लेवल–2' से बढ़ाकर अब 'लेवल–3' कर दिया गया है। हवाई अड्डे को जुलाई 2024 में 'लेवल–2' की मान्यता मिली थी।

'हवाई अड्डा ग्राहक अनुभव मान्यता' दरअसल अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र परिषद द्वारा विकसित एक बहु–स्तरीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्राहक अनुभव प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हवाई अड्डों का मार्गदर्शन करना है।

बयान में कहा गया है कि 'लेवल–3' की यह मान्यता हवाई अड्डा संस्कृति, शासन, परिचालन संबंधी सुधार, मापन, ग्राहक रणनीति और ग्राहकों की जरूरतों को समझने जैसे मानकों के आधार पर दी जाती है।

हवाई अड्डे ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और

सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें लागू की हैं। इनमें यात्रियों के लिए जलपान और व्यावसायिक केंद्रों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ डिजी यात्रा, त्वरित आव्रजन सुविधा और इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश द्वारों जैसी आधुनिक तकनीकों का समावेश प्रमुख है।

बयान के मुताबिक, 'मेड इन इंडिया' रोबोट के माध्यम से स्वचालित सफाई प्रणाली का उपयोग भी यात्रियों की सुविधा बढ़ाने में सहायक रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे के कामकाज में कई बदलाव किए गए हैं।

भारत का कौन–सा शहर कहलाता है 'City of Honey'...क्या आप जानते हैं इसका नाम?

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

हर शहर की अपनी एक अलग कहानी होती है। दुनिया भर में कुछ जगहें अपने लजीज खाने के लिए मशहूर हैं, तो कुछ अपनी शानदार संस्कृति और कुदरती खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जिसका नाम ही उसकी 'मिठास' पर रखा गया हो?

उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला एक ऐसी ही खास जगह है। यहां की हवाओं में फूलों की महक और खेतों में मधुमक्खियों की गूंज है। बड़े पैमाने पर शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन के कारण ही इस जिले को 'City of Honey' का खूबसूरत खिताब मिला है। जी हां, यह शहर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख 'हनी हब' है। आइए जानते हैं कि आखिर महाराजगंज में ऐसा क्या खास है जो इसे यूपी का 'स्वीट स्पॉट' बनाता है।

उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला अपने बड़े पैमाने पर शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। यहां के स्थानीय किसानों और लोगों के लिए यह केवल एक काम नहीं, बल्कि उनकी जीवनशैली और अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यहां शहद, मोम और मधुमक्खी से जुड़े अन्य उत्पादों से लोगों को अच्छी आमदनी होती है। इसी वजह से यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख 'हनी हब' बन गया है।

यह जिला भारत–नेपाल सीमा के पास और गोरखपुर मंडल का हिस्सा है।

यहां साल भर फूल, खेत और प्राकृतिक हरियाली रहती है। यहां गन्ने, सरसों, फलों के पेड़ और हरे–भरे गांवों की भरमार है।

यह उपजाऊ भूमि और अनुकूल मौसम मधुमक्खियों को पनपने और शहद बनाने के लिए बेहतरीन माहौल प्रदान करते हैं। महाराजगंज में शहद उत्पादन के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। किसान अपने मधुमक्खी के बक्से खेतों, बागों और जंगलों के पास रखते हैं। मधुमक्खियां अलग–अलग स्रोतों से रस इकट्ठा करती हैं, जैसेःसरसों, लीची, सूरजमुखी, जंगली फूल।

यही कारण है कि यह जिला अपने 'मल्टी–लावर हनी' के लिए जाना जाता है, जो अपने प्राकृतिक स्वाद और शुद्धता के लिए मशहूर है।

उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख शहद उत्पादक राज्यों में से एक है, जिसमें महाराजगंज और सहारनपुर जैसे जिले अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छी फसलें, अनुकूल मौसम और सरकारी सहायता ने यहां शहद उत्पादन को बहुत बढ़ावा दिया है। यहां का शहद केवल स्थानीय बाजारों तक ही सीमित नहीं है। भारत से यूरोप, खाड़ी देशों और दक्षिण–पूर्व एशिया में शहद का निर्यात किया जाता है और इस व्यापार में महाराजगंज का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।

4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस पर जानिए नेत्रहीनों के लिए 'ब्रेल लिपि' का निर्माण करने वाले लुई ब्रेल कौन थे

नई दिल्ली, 03 जनवरी।

4 जनवरी सन् 1809 में फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किमी दूर कूपरे नामक गांव में लुई ब्रेल (लुइस ब्रेल) का जन्म हुआ था। लुई ब्रेल स्वयं दृष्टिहीन थे। लुई चार भाई–बहनों में सबसे छोटे थे। लुई की माता मोनिक ब्रेल एक घरेलू महिला तथा पिता सायमन ब्रेल घोड़ों की जीन बनाने का एक कारखाना चलाते थे।

लुई ने अपने आसपास ऐसे बहुत–से लोग देखे होंगे जिनकी आंखें तो हैं, पर दृष्टि या नजर नहीं है अर्थात् आंखें होने के बावजूद वे कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। आज हम ऐसे दृष्टिहीन लोगों को बहुत सामर्थ्य के साथ अनेक जगहों पर काम करते हुए देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अंधे व्यक्ति या तो किसी के आश्रित होते थे या उन्हें भीख मांगकर अपना जीवन गुजारना पड़ता था। फ्रांस के लुई ब्रेल ने स्वयं एक दृष्टिहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ने–लिखने के योग्य बनाया। सामान्य बच्चे या तो रोमन लिपि में पढ़ते हैं या देवनागरी लिपि में, लेकिन दृष्टिहीन बच्चों के पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने एक अलग लिपि विकसित की और उसे ब्रेल लिपि नाम मिला।

जब लुई ब्रेल महज 3 साल के थे, तब एक दिन खेलते–खेलते उन्होंने जीन के लिए चाकू से चमड़ा काटने का प्रयास किया लेकिन चाकू आंख में जा लगा और लुई की एक आंख हमेशा के लिए दृष्टिहीन हो गई। उस आंख में हुए संक्रमण की वजह से कुछ दिनों बाद उन्हें दूसरी आंख से भी दिखना बंद हो गया और वे पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए। लुई के जीवन 7 वर्ष ऐसे ही गुजरे, 10 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवा दिया। उस स्कूल में वेलंटीन होउ द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, पर यह लिपि अधूरी थी।

लुई ने यहां इतिहास, भूगोल और गणित में कुशलता

हासिल की थी। इसी स्कूल में एक बार फ्रांस की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बार्बियर एक प्रशिक्षण के सिलसिले में आए और उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली 'नाइट राइटिंग' या 'सोनोग्राफी' लिपि के बारे में बताया। यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती थी और इसमें 12 बिंदुओं को 6–6 की दो पंक्तियों को रखा जाता था, पर इसमें विराम चिह्न, संख्या, गणितीय चिह्न आदि का अभाव था।

प्रखर बुद्धि के लुई ने इसी लिपि को आधार बनाकर 12 की बजाय मात्र 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षर और चिह्न बनाए और उसमें न केवल विराम चिह्न बल्कि गणितीय चिह्न और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। यही लिपि आज सर्वमान्य है। मात्र 15 वर्ष के उम्र में लुई ने यह लिपि बनाई।

सन् 1851 में लुई ब्रेल की तबियत बिगड़ने लगी और 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण करने वाले लुई ब्रेल की याद में 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि लुई ब्रेल के अथक प्रयासों की वजह से ही नेत्रहीनों को पढ़ने का मौका मिला। उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है।